



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 342]
No. 342]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 1981/आश्विन 24, 1903
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 1981/ASVINA 24, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

द्वितीय मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 1981

प्राय-कर

सा० का० नि० 559(अ) :- प्राय कर करों से संबंधित दोहरे कराधान के परिवर्जन के लिए और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य सरकार और संयुक्त तंजानिया गणराज्य सरकार के बीच करार का, जो उपाबद्ध है, अनुसमर्थन कर दिया गया है और उक्त करार के अनुच्छेद 30 की अपेक्षा के अनुसार अनुसमर्थन लिखतों का आदान-प्रदान हो गया है।

अन., केन्द्रीय सरकार, प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कम्पनी (लाभ) प्रतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24-क द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निवेदन करती है कि उक्त करार के सभी उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।

उपबंध

[फा० सं० 501/18/73-एफ टी डी]

र० रा० खोसला, प्रवर सचिव

प्राय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारतीय गणराज्य की सरकार और संयुक्त तंजानिया गणराज्य की सरकार के बीच

करार

भारतीय गणराज्य की सरकार

तथा

संयुक्त तंजानिया गणराज्य की सरकार

के बीच

प्राय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

करार

भारतीय गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त तंजानिया गणराज्य सरकार प्राय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए करार सम्पन्न करने की इच्छा से नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है :

अध्याय- I**करार का अर्थ****अनुच्छेद I****व्यक्तिगत क्षेत्र**

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद- 2

1. यह करार जिन करों पर लागू होगा, वे हैं ?

(क) भारत के मामले में :

(1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन लगाया गया आयकर जिसमें आय-कर पर कोई अधिभार भी शामिल है

(2) कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अधीन लगाया गया अधिकर : (जिसे इसके बाद 'भारतीय कर' कहा गया है)।

(ख) तंजानिया के मामले में :

आयकर और आयकर अधिनियम, 1973 के अधीन आयकर समझा जाने वाला कोई अन्य कर (जिसे इसके बाद "तंजानियाई कर" कहा गया है)।

2. यह करार, किन्हीं समूह अथवा सारतः जैसे ही करों पर भी लागू होगा जो दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर, वर्तमान करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बाद लगाये गए हों।

3. प्रत्येक वर्ष के अन्त में, संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने उन कराधान कानूनों में किये गये उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो इस करार के विषय हैं और संगत अधिनियमनों और विनियमों की प्रतियां भेजेंगे।

अध्याय- II**परिभाषाएं****अनुच्छेद-3****सामान्य परिभाषाएं**

1. इस करार में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो :

(क) 'भारत' शब्द से अभिप्रेत है भारत का क्षेत्र और उसमें प्रादेशिक समूह और उसके ऊपर भाकाशी क्षेत्र तथा प्रादेशिक समूह, महा-द्वीपीय जल सीमा, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्या 80) में उल्लिखित कोई भी अन्य ऐसा समुद्री क्षेत्र शामिल है, जिसमें भारत के कतिपय अधिकार हों और उस सीमा तक उनमें इन अधिकारों का उसी प्रकार प्रयोग किया जा सकता है मानो वह समुद्री क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र का एक भाग हो ;

(ख) "तंजानिया" शब्द से अभिप्रेत है संयुक्त तंजानिया गणराज्य और उसमें तंजानिया के प्रादेशिक समूह से बाहर वह क्षेत्र भी शामिल है जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, महाद्वीपीय जल सीमा के सम्बन्ध में तंजानिया कानून के अधीन ऐसे क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है अथवा किया जा सकता है, जिस पर प्राकृतिक संसाधनों को खोज निकालने तथा उनको

उपयोग में लाने के लिए तंजानिया अपने प्रभु सत्ता सम्पन्न अधिकारों का प्रयोग कर सकता है ;

(ग) "संविदाकारी राज्य" और "दूसरे संविदाकारी राज्य" शब्दों से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा तंजानिया अभिप्रेत है ;

(घ) "कर" शब्द से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय कर अथवा तंजानिया का कर अभिप्रेत है किन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के सम्बन्ध में ऐसी किसी एक अथवा मूल के सम्बन्ध में देय हो जिन पर यह करार लागू होता है अथवा जो ऐसे अर्थव्यवस्था की रकम हो जो उन करों के सम्बन्ध में लगाया गया हो ;

(ङ) 'व्यक्ति' शब्द में वे व्यक्ति, कम्पनियां और सभी अन्य सत्ताएं शामिल हैं जिन्हें अपने अपने संविदाकारी राज्य में लागू कराधान कानूनों के अधीन कर योग्य एककों के रूप में समझा जाता है ;

(च) 'कम्पनी' शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई इकाई अभिप्रेत है जो अपने-अपने संविदाकारी राज्य के लागू कराधान कानूनों के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में मानी जाती है ;

(छ) 'एक संविदाकारी राज्य का उद्यम' तथा 'दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम' शब्दों से क्रमशः संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा संचालित उद्यम अभिप्रेत है ;

(ज) 'सक्षम प्राधिकारी' शब्द से अभिप्रेत है, भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) और तंजानिया के मामले में वित्त मंत्री अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(झ) "राष्ट्रकों" शब्द से अभिप्रेत है ;

(1) संविदाकारी राज्य की राष्ट्रियता धारण करने वाले सभी व्यक्ति ;

(2) सभी विधिक व्यक्ति, भागीदारियां और संस्थाएं जो संविदाकारी राज्य के प्रवृत्त कानून से इस प्रकार अपनी हैसियत प्राप्त करते हैं।

2. संविदाकारी राज्यों में से किसी एक द्वारा इस करार के उपबन्धों के प्रवर्तन में किसी भी पक्ष का, जो यहां परिभाषित नहीं हुआ हो, संदर्भ की अन्यथा अपेक्षा नहीं होने पर, वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से सम्बन्धित कानूनों के अन्तर्गत होता है जो इस करार के विषय हैं।

अनुच्छेद 4**प्राधिकृत अधिवास**

1. इस करार के प्रयोजन से, "संविदाकारी राज्य का निवासी" शब्दों से अभिप्रेत, ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो उस राज्य के कानून के अनुसार, अपने अधिवास, निवास, प्रबन्ध का स्थान अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य कसौटी के कारण उसमें कर लगने योग्य है।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण, कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो इस करार के प्रयोजनों के लिये उसकी निवासी हैसियत निम्नलिखित नियमों के अनुसार निर्दिष्ट की जायगी :-

(क) वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायगा जहां उसका स्थायी निवास-गृह हो। यदि उसका दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थायी निवास-गृह हो तो वह उस संविदाकारी राज्य

का निवासी माना जायेगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और धार्मिक सम्बन्ध अनिच्छित हैं (जिसे इसके बाद 'महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र' के रूप में उल्लेख किया जायेगा);

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसका किसी भी संविदाकारी राज्य में स्थायी निवास-गृह नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा जिसमें उसका व्यावहारिक आवास हो;

(ग) यदि उसका व्यावहारिक आवास संविदाकारी दोनों राज्यों में है अथवा इनमें से किसी भी राज्य में नहीं है, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा जिसका वह राष्ट्रिक है;

(घ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहाँ व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के अनुसार दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध है।

अनुच्छेद 5

स्थायी स्थापन

1. इस करार के प्रयोजन के लिए, "स्थायी स्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहाँ उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. "स्थायी स्थापन" पद में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) प्रबन्ध का स्थान;
- (ख) शाखा;
- (ग) कार्यालय;
- (घ) कारखाना;
- (ङ) कर्मशाला;
- (च) खान, खदान, तेल का क्षेत्र अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का अन्य स्थान;
- (छ) फार्म, बागान अथवा अन्य स्थान जहाँ कृषि, जंगल, बागान अथवा सम्बन्धित कार्यकलाप चलाये जा रहे हों;
- (ज) भवन स्थल अथवा निर्माण अथवा सामूहिक परियोजना अथवा उसके सम्बन्ध में पर्यवेक्षण कार्यकलाप, जहाँ इस प्रकार का स्थल, परियोजना अथवा पर्यवेक्षण कार्यकलाप छ: महीने से अधिक अवधि के लिए चलाये जाते हों।

3. "स्थायी स्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जायेगा:

- (क) उद्यम के माल अथवा पत्नी के केवल अण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग;
- (ख) उद्यम के माल अथवा पत्नी के केवल अण्डारण-अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ स्टाक रखना;
- (ग) अन्य उद्यम द्वारा केवल प्रतिनिधि तैयार करने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पत्नी का स्टाक रखना;

(घ) उद्यम के लिए माल अथवा पत्नी के केवल ऋण अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार के नियत स्थान का अण्डारण;

(ङ) उद्यम के व्यापार अथवा कारोबार में विज्ञापन, सूचना देने अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों के अन्य प्रयोजनार्थ औ प्रारंभिक अथवा सहायक किस्म के हों, कारोबार के नियत स्थान का अण्डारण।

4. अन्य संविदाकारी राज्य के उद्यम के लिए अथवा उद्यम की ओर से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति जो स्वतंत्र हैसियत के अधिकारों से भिन्न हो और जिस पर पैराग्राफ 5 के उपबन्ध लागू होते हों - प्रयोज्य राज्य में उस उद्यम का स्थायी स्थापन माना जायेगा, यदि:

(i) वह उस राज्य में उस उद्यम के लिए अथवा उद्यम की ओर से संविदा करने का प्राधिकार रखता है और उसका नियमित रूप से प्रयोग करता है, जबकि उसके क्रियाकलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा पत्नी के ऋण तक ही सीमित नहीं हों; अथवा

(ii) वह प्रयोज्य संविदाकारी राज्य में, उस उद्यम के माल अथवा पत्नी का ऐसा स्टाक प्रायः रखता है, जिसमें से वह उस उद्यम की ओर से नियमित रूप से धारकों की पूति करता है।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का अन्य संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण से स्थायी स्थापन नहीं माना जायेगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी बलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, जहाँ ऐसे व्यक्ति अपना कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। किन्तु, जब इस प्रकार के एजेंट के क्रियाकलाप उस उद्यम की ओर से पूर्णरूप से अथवा लगभग पूर्णरूप से किये जाते हैं तो उसे इस पैराग्राफ के अर्थ के अन्तर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं माना जायेगा।

6. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी, जो संविदाकारी राज्यों में से एक की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियंत्रण करती है, अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) व्यापार अथवा कारोबार चलाती है, उन दोनों कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी स्वतः दूसरी कम्पनी का स्थायी स्थापन नहीं बन जायेगी।

7. किसी संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी स्थापन माना जायेगा यदि वह दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कारोबार चलाता है जिसमें शोक मनोरंजनकलाओं (जैसे रंग-मंच, चलचित्र, रेडियो अथवा टेलीविजन कलाकारों और संगीतज्ञों) अथवा खिलाड़ियों की सेवार्थ प्रदान करना शामिल हो; जब तक कि ऐसी सेवाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में उद्यम के प्रयोज्य संविदाकारी राज्य की सरकार की राजकीय विधियों से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से सहायता नहीं भी जाती है।

अध्याय-III

धारा का करारधान

अनुच्छेद-6

अच्छल संपत्ति से आय

1. अच्छल संपत्ति से आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जायेगा जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित हो।

2 'अचल सम्पत्ति' शब्दों की परिभाषा उस संविदाकारी राज्य की विधि और व्यवहार के अनुसार दी जाएगी, जिसमें सम्बन्धित सम्पत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे— अचल सम्पत्ति के उपसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वन-सम्पत्ति में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति सम्बन्धी सामान्य कानून के उपबन्ध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार, खनिज भण्डार, तेल-कूप, खदान तथा प्राकृतिक ससाधनों के निकर्षण के अन्य स्थानों का सञ्चालन-अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार। पोत तथा विमान अचल सम्पत्ति नहीं माने जायेंगे।

3 पैराग्राफ 1 के उपबन्ध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग से, किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे।

4 पैराग्राफ 1 और 3 के उपबन्ध किसी उद्यम की व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन के लिए इस्तेमाल में आने वाली अचल सम्पत्ति से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद-7

कारोबार से लाभ

1 एक संविदाकारी राज्य का उद्यम, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में, वहाँ स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता हो, तो तो उस उद्यम के लाभ केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे। यदि उद्यम पूर्वोक्त प्रकार से कारोबार कर रहा हो तो उद्यम के लाभों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा-सकेगा परन्तु केवल उतने ही लाभों पर जो उस स्थायी स्थापन के कारण हुए माने जा सकते हैं।

2 यदि एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम, जिसका संविदाकारी राज्य में स्थायी स्थापन है वैसे ही अथवा उसी प्रकार का माल अथवा बन्ध बेचता है वैसे ही कि स्थायी स्थापन द्वारा बेची जाती है अथवा वैसे ही अथवा उसी प्रकार की सेवाएँ प्रदान करता है वैसे ही स्थायी स्थापन करता है, तो इस प्रकार के क्रियाकलापों से होने वाले लाभों को तब स्थायी स्थापन के कारण होना माना जाएगा जब तक कि उद्यम यह सिद्ध नहीं करता है कि ऐसी विश्वी अथवा सेवाएँ स्थायी स्थापन के क्रियाकलाप के कारण नहीं मानी जा सकती हैं।

3 जहाँ एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में, वहाँ स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, वहाँ प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी स्थापन के कारण उसको उस लाभ का होना माना जायेगा जिनके प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती है, जब वह, उन्हीं अथवा वैसे ही अथवा के अधीन, उन्हीं अथवा वैसे ही कार्यों में सगा हुआ स्वतन्त्र तथा अलग उद्यम होता, और जिस उद्यम का वह स्थायी स्थापन है, उसके साथ पूर्णतः स्वतन्त्र रूप से व्यवहार करता होता। किसी भी अवस्था में, जहाँ स्थायी स्थापन के कारण हुए माने जा सकने वाले लाभों की सही रकम निर्धारित नहीं की जा सकती हो अथवा उसका पता लगाना बहुत ही कठिन हो, तो स्थायी स्थापन के कारण हुए माने जा सकने वाले लाभों का अनुमान उपयुक्त आधार पर लगाया जाए।

4 जहाँ किसी संविदाकारी राज्य में, उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न भागों के प्रति अनुभाजन के आधार पर, किसी स्थायी स्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों को निर्दिष्ट करने की प्रथा हो, वहाँ पैरा-ग्राफ 3 की कोई भी व्याख्या उस संविदाकारी राज्य को ऐसी यथा कृपि प्रभाजन पद्धति से कर-लगने वाले लाभों को निर्दिष्ट करने से निर्धारित नहीं करेगी; तथापि अन्यायी गई प्रभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों के अनुसार होगा।

5 किसी स्थायी स्थापन के लाभों के निर्धारण में उन व्ययों को कटौतियों की स्वीकृति दी जायेगी जो स्थायी स्थापन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए किए गए हों और उनमें इस प्रकार किए गए कार्यवालीय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहाँ स्थायी स्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र, किन्तु इसमें वह व्यय शामिल नहीं है जिनकी उस राज्य के कानून के अनुसार उस राज्य के किसी उद्यम द्वारा कटौती किये जाने की अनुमति नहीं है।

6 कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी स्थापन को हुए नहीं माने जायेंगे कि उस स्थायी स्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पथ वस्तुएँ खरीदी हैं।

7 पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिये स्थायी स्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों को तब तक उसी पद्धति से वर्णानुवर्ण निर्धारित किया जायगा जब तक कि उसके विरुद्ध कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण न हो।

8. 'कारोबार से लाभ' पद का अर्थ चलाए जा रहे कारोबार ने उद्यम द्वारा प्राप्त आय है; किन्तु इसमें किराया, रायल्टी (जिसमें मिनेमा फिल्डों अथवा टेलीविजन के बीडियो टेप के सम्बन्ध में किराया अथवा रायल्टी शामिल है) तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, प्रबन्ध व्यय अथवा तकनीकी अथवा अन्य कामों की सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए पारिश्रमिक अथवा फीस, ब्याज लाभांश, पूँजीगत लाभ श्रमिक के लिए पारिश्रमिक अथवा व्यक्तिगत सेवाएँ अथवा पोतों अथवा वायुयानों के सञ्चालन से होने वाली आय भी शामिल हैं।

अनुच्छेद-8

विमान परिवहन

1 एक संविदाकारी राज्य के उद्यम को अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में विमान परिवहन से प्राप्त लाभों पर कर उस संविदाकारी राज्य में ही लगाया जायेगा जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबन्ध का स्थान स्थित है।

2 इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबन्ध, संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा किसी संयुक्त विमान परिवहन संचालन अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संचालक एजेंसी में मूल सेवा में भाग लेने से अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान संचालन से होने वाले लाभों के भाग पर भी लागू होंगे।

3 पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिये, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान संचालन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध निधियों पर ब्याज को ऐसे वायुयान के संचालन से होने वाली आय के रूप में माना जायेगा और अनुच्छेद 12 के उपबन्ध, इस प्रकार ब्याज के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद-9

जहाजरानी

1 संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के उद्यम को दूसरे संविदाकारी राज्य से अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोत परिवहन से हुई आय पर उन दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, लेकिन ऐसी आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रभावी कर की उस कर की 50 प्रतिशत के बराबर रकम में से घटा दिया जायेगा।

2 इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिए पोतों के संचालन से दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राप्त आय का अर्थ उस दूसरे संविदाकारी राज्य से जलपोतों द्वारा भेजे गए यात्रियों, शक, पशुधन अथवा माल को ले जाने से होने वाली आय से होगा।

3 पैराग्राफ 1 तदवर्ती यातायात के परिणाम उत्पन्न होने वाले लाभों पर लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद-10

संबन्ध उपक्रम

जहाँ

- (क) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के उपक्रम के प्रबन्ध, नियन्त्रण अथवा पूंजी में, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा
- (ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध, नियन्त्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं,

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उपक्रमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय सम्बन्धों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो वैसी शर्तों से भिन्न हैं, जैसी स्वतन्त्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहाँ ऐसा कोई लाभ जो उन शर्तों के न होने की हालत में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता किन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुआ तो वह लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा और वे तदनुसार कराधेय हो सकेंगे।

अनुच्छेद-11

लाभांश

1. जो कम्पनी एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किये गये लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।

2. किन्तु इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारी राज्य में भी कराधेय होंगे जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है, और यह कर उस राज्य के कानून के अनुसार लगाया जायेगा, किन्तु इस प्रकार लगाये जाने वाले कर की रकम मिन्मलिखित से अधिक नहीं होगी :—

- (क) लाभांशों की सकल रकम का 10 प्रतिशत, यदि प्राप्तकर्ता एक ऐसी कम्पनी है जो लाभांशों की अदायगी की तारीख के तत्काल पूर्ववर्ती छः महीनों की अवधि में लाभांशों की अदायगी करने वाली कम्पनी के कम से कम 10 प्रतिशत शेयरों का स्वामित्व रखती हो ;
- (ख) अन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल राशि का 15 प्रतिशत।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "लाभांशों" पद का अभिप्राय, शेयरों अथवा लाभों में भागीदारी के अन्य अधिकारों से, जो ऋण-दावों के सम्बन्ध में न हों, प्राप्त भाय से तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त हे ऐसी भाय से है जो शेयरों अथवा किसी अन्य मद से होने वाली भाय में सम्मिलित हो और जो उस संविदाकारी राज्य कराधान कानून द्वारा, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है, कम्पनी का लाभांश अथवा वितरण समझा जाता है।

4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांश प्राप्त करने वाला, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में व्यापार करता है जिस की, लाभांश अदा करने वाली कम्पनी, वहाँ स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से, निवासी है अथवा वह कम्पनी उस राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से उस दूसरे राज्य में व्यवसाय सम्बन्धी सेवाएं निष्पन्न करती है और जिस धारिता के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्धित है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 16, जैसा भी मामला हो, के उपबन्ध लागू होंगे।

5. जहाँ कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा भ्राम प्राप्त करती है, वहाँ कम्पनी द्वारा उन व्यक्तियों को दिये गये लाभांशों पर जो उस दूसरे राज्य के निवासी नहीं हैं, उस दूसरे राज्य में कोई कर नहीं लगाया जायगा अथवा कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ-कर की किस्म का कोई कर नहीं लगाया जायगा, चाहे दिया गया लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा भाय के रूप में ही हो।

अनुच्छेद-12

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किये जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जायेगा।

2. किन्तु, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जायेगा जिस राज्य में यह प्रजित होता है, किन्तु इस प्रकार प्रभारित कर की रकम ब्याज की सकल राशि के 12½ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के बावजूब, एक संविदाकारी राज्य में प्रजित होने वाले अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार को अथवा उसके स्थायी प्राधिकरण को उस दूसरे संविदाकारी राज्य के सैप्टल बैंक अथवा उस सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली किसी एजेंसी को प्रवत ब्याज पर प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य के कर से छूट दी जायेगी।

संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, परस्पर सहमति से, किसी भी अन्य सरकारी संस्थान को निर्धारित कर सकते हैं जिस पर यह पैरा-ग्राफ लागू होता है।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से, सरकारी प्रति-भूतियों, बन्ध-पत्रों अथवा ऋण पत्रों, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं, और चाहे उनको लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं, और हर प्रकार के ऋण-दावों से प्राप्त भाय और साथ ही सभी अन्य ऐसी भाय से अभिप्राय है, जो, जिस संविदाकारी राज्य में भाय उत्पन्न हुई हो, उस राज्य के कराधान कानून के अनुसार, उधार दिये गये धन से प्राप्त भाय में समाविष्ट की गयी हो।

5. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज-प्राप्तकर्ता, संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से, व्यापार चलाता हो, अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित निश्चित स्थान से स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं करता हो, और जिस ऋण दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी प्रतिष्ठान अथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 16 के उपबन्ध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज उत्पन्न हुआ माना जायेगा, यदि ब्याज अदा करने वाला स्वयं संविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक उप-मंडल, कोई स्थानीय प्राधिकारी अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु, जहाँ ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में इसका स्थायी प्रतिष्ठान है, जिसके सम्बन्ध में वह ऋण लिया गया था जिस पर ब्याज की अदायगी की गई है और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा अदा किया जाता है तब वह ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उत्पन्न माना जायेगा जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है।

7. जहाँ ब्याज, भ्रदा करने वाले तथा प्राप्तकर्ता के बीच, भ्रयवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण, भ्रदा की गयी ब्याज की रकम, उस ध्वन-दावे की ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम भ्रदा की गयी है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिये इस प्रकार के सम्बन्ध नहीं होने की स्थिति में, भ्रदा करने वाला और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गयी होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम धर्गित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, भ्रदायगी के प्रतिरिक्त भाग पर, इस करार के अन्य उपबन्धों का अनुपालन करने हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-13

रायल्टियाँ

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को भ्रदा की गयी रायल्टियों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. किन्तु ऐसी रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, जिसमें वे उद्भूत होती हैं, और उस राज्य के कानून के अनुसार, किन्तु इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रायल्टियों की कुल रकम के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त 'रायल्टियाँ' शब्द से साहित्यिक, कलात्मक भ्रयवा वैज्ञानिक कृतियों (जिनमें चलचित्र फिल्में तथा रेडियो भ्रयवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में भ्रयवा टेपें भी शामिल हैं), कोई पेटेन्ट, व्यापार-चिन्ह, डिजाइन भ्रयवा माडल, प्लान, गुप्त फार्मूला भ्रयवा प्रक्रिया के प्रयोग भ्रयवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में भ्रयवा औद्योगिक, वाणिज्यिक भ्रयवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग के लिए भ्रयवा प्रयोगाधिकार के लिए भ्रयवा औद्योगिक, वाणिज्यिक भ्रयवा वैज्ञानिक अनुभव से सम्बन्धित जानकारी के लिए प्राप्त किसी प्रकार की भ्रदायगी अधिप्रेत है।

4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध उस हालत में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टी प्राप्तकर्ता, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियाँ उद्भूत होती हैं वहाँ पर स्थित स्थायी प्रतिफल के माध्यम से व्यापार चलाता है भ्रयवा उस दूसरे राज्य में वहाँ पर स्थित एक निर्धारित स्थान से व्यावसायिक सेवाएं करता है, तथा जिस अधिकार भ्रयवा सम्पत्ति के बारे में रायल्टियों की भ्रदायगी की जाती है, वह उक्त स्थायी प्रतिष्ठान भ्रयवा निश्चित स्थान से कारणरूप से सम्बन्धित है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 भ्रयवा अनुच्छेद 16 के उपबन्ध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

5. किसी संविदाकारी राज्य में रायल्टियाँ उद्भूत हुई मानी जायेंगी यदि रायल्टी भ्रदा करने वाला स्वयं संविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक उप-मंडल, कोई स्थानीय प्राधिकरण भ्रयवा उस राज्य का कोई निवासी हो परन्तु, जहाँ रायल्टियाँ भ्रदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी ही भ्रयवा नहीं एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है जिसके सम्बन्ध में रायल्टी भ्रदा की गयी थी और इस प्रकार की रायल्टियाँ उस स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा उद्भूत हुई हैं, तब ऐसी रायल्टियाँ उक्त संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जायेंगी, जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है।

6. जहाँ, रायल्टी भ्रदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच भ्रयवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण, भ्रदा की गयी रायल्टियों की रकम, उसके ऐसे हस्तमाल, अधिकार भ्रयवा सूचना को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए वह रायल्टी भ्रदा की जाती है, उस रकम से बढ़ जाती है जिस के लिये इस प्रकार के सम्बन्ध न होने की स्थिति में भ्रदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच

सहमति हो गयी होती वहाँ इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम धर्गित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, भ्रदायगीयों के अधिभाग पर इस करार के अन्य उपबन्धों का अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जायेगा।

अनुच्छेद-14

पूर्वीगत लाभ

1. प्रथम सम्पत्ति के अन्तर्ण से होने वाले लाभ, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित, उस संविदाकारी राज्य में कराधेय हो सकेंगे जिसमें ऐसी सम्पत्ति स्थित है।

2. अल सम्पत्ति के अन्तर्ण से, जो उस स्थायी प्रतिष्ठान की व्यापारिक सम्पत्ति के अंग के रूप में एक संविदाकारी राज्य के उद्यम की तरह दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है, भ्रयवा किसी निश्चित स्थान से सम्बन्धित अल सम्पत्ति के अन्तर्ण से, जो एक संविदाकारी राज्य के निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, होने वाले लाभ पर, जिसमें ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान (अकेले भ्रयवा सम्पूर्ण उद्यम के साथ) भ्रयवा ऐसे निर्धारित स्थान के अन्तर्ण से होने वाले लाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा ऐसे चल-पौतों तथा वायु यान के अन्तर्ण से जिन्हें एसा उद्यम अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के अन्तर्गत परिचालन करता है तथा इस प्रकार के जल-पौतों तथा वायुयानों के संचालन में सम्बन्धित अल सम्पत्तियों से प्राप्त लाभ केवल उस राज्य में कराधेय होंगे।

4. संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, पैराग्राफ 1, 2 तथा 3 में उल्लिखित सम्पत्ति से अल किसी सम्पत्ति के अन्तर्ण से प्राप्त लाभ केवल उसी राज्य में कराधेय होंगे।

5. 'अन्तर्ण' शब्द का अर्थ सम्पत्ति का विक्रय, विनियम, अन्तर्ण भ्रयवा उसमें किसी भी अधिकार की समाप्ति भ्रयवा अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में प्रभूत किसी भी कानून के अन्तर्गत उसका अनिर्णय अधिग्रहण है।

अनुच्छेद-15

प्रबन्ध फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को भ्रदा की गयी प्रबन्ध व्यवस्था भ्रयवा वृत्ति सम्बन्धी फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. लेकिन इस प्रकार के प्रबन्ध भ्रयवा वृत्ति सम्बन्धी फीसों पर उस संविदाकारी राज्य में जिसमें वे उद्भूत होती हैं, पर उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा किन्तु इस प्रकार लगाये गये कर की रकम प्रबन्ध भ्रयवा वृत्ति सम्बन्धी फीसों की सकल रकम के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त 'प्रबन्ध-व्यवस्था भ्रयवा वृत्ति-सम्बन्धी फीस के शब्दावली का अर्थ, भ्रदायगी करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी से हस्तगत व्यक्तियों को प्रबन्धकीय, तकनीकी भ्रयवा परामर्शदायी किस्म की किन्हीं सेवाओं के प्रतिफल के रूप में की जाने वाली किसी भी प्रकार की भ्रदायगियाँ हैं।

4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे यदि प्रबन्ध भ्रयवा वृत्ति-संबन्धी फीस प्राप्त करने वाला, एक संविदाकारी राज्य होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें प्रबन्ध भ्रयवा वृत्ति-संबन्धी फीस उद्भूत होती है, स्थित स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से, व्यापार करत

है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से वृत्ति संबंधी सेवाएं करता है, और जिस अधिकार अथवा संपत्ति से संबद्ध प्रबन्ध अथवा व्यवसाय-संबंधी फीस अथवा की जाती है, वह इस प्रकार से स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 16, जैसी भी स्थिति हो, संबंधी उपबन्ध लागू होंगे।

5. प्रबन्ध अथवा वृत्त संबंधी फीस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई तब मानी जायेगी जब कि भ्रदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक उप-मंडल, कोई स्थानीय प्राधिकारी अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु, जहाँ प्रबन्ध अथवा वृत्ति-संबंधी फीस भ्रदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह उस राज्य का निवासी हो अथवा नहीं एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है जिसके संबंध में प्रबन्ध अथवा वृत्ति संबंधी फीस भ्रदा की गयी थी और प्रबन्ध अथवा वृत्ति संबंधी ऐसी फीस इस प्रकार के स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा वहन की जाती है तो ऐसी प्रबन्ध अथवा वृत्ति संबंधी फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जायेगी जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है।

6. जहाँ, भ्रदा करने वाले तथा प्राप्त करने वाले के बीच अथवा उन दोनों तथा किसी दूसरे व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण प्रबन्ध अथवा वृत्ति-संबंधी फीस की भ्रदा की गयी रकम, उन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जिनके लिए फीस की भ्रदायगी की गयी है, उस रकम से बढ़ जाती है जिसके बारे में, इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में, भ्रदा करने वाला तथा प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गई होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अंतिम बर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसी स्थिति में, भ्रदा की गई रकमों के अधिक भाग, पर, इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखकर, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनो के अनुसार कर लगाया जायगा।

अनुच्छेद 16

स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं

1. अनुच्छेद 15 के उपबंधों के अधीन एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, वृत्ति-संबंधी सेवाओं अथवा इसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त भाय पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा जब तक कि :—

- (क) अपने कार्यकलापों के प्रयोजनों के निमित्त उसे दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध न हो, जिस मामले में उस दूसरे राज्य में उतनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती हो; अथवा
- (ख) वह भाय के संगत वर्ष में कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए, अपने कार्यकलापों के प्रयोजन के निमित्त, दूसरे संविदाकारी राज्य में उपस्थित रहा हो और ऐसी स्थिति में उस दूसरे राज्य में उतनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे राज्य में किये गये कार्यकलापों के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती हो।

2. 'वृत्ति संबंधी सेवाएं' शब्द में स्वतन्त्र वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, शैक्षणिक अथवा प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, दकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, वंश-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतन्त्र कार्य-काप भी शामिल है।

अनुच्छेद 17

पराभित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 18, 19, 20, 21, 22 तथा 23 के उपबंधों के अधीन एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, नियोजन के संबंध में, प्राप्त वेतन, मजूरी तथा अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में

लग सकेगा जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं हो। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में हो तो उससे प्राप्त पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, दूसरे संविदाकारी राज्य में नियोजन के संबंध में, प्राप्त पारिश्रमिक पर कर, केवल प्रथम उल्लिखित राज्य में ही लगेगा यदि

- (क) प्राप्त कर्ता भाय के संगत वर्ष में कुल मिलाकर 183 दिन की अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद रहा है, और
- (ख) पारिश्रमिक की भ्रदायगी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से की गई हो जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है, और
- (ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया गया हो, जो कि उस नियोजक का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलपोत पर अथवा वायुयान पर किये गये नियोजन के संबंध में पारिश्रमिक पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिस में उस उद्यम की प्रभावी प्रबन्ध व्यवस्था है।

अनुच्छेद 18

निदेशक मुक्त

संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल के एक सदस्य की हैसियत से, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, प्राप्त निदेश की फीस तथा इसी प्रकार की भ्रदायगियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 19

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 16 तथा 17 के उपबंधों के होते हुए भी, लोक मनोरंजन-कर्ताओं (जैसे, थियेटर, चल-चित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार तथा संगीतकार) अथवा खिलाड़ियों को अपनी हैसियत से अपने वैयक्तिक कार्यों से प्राप्त भाय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमें ऐसे कार्य किये गये हों:

किन्तु ऐसी भाय पर जबत संविदाकारी राज्य में कर नहीं लग सकेगा यदि लोक मनोरंजनकर्ताओं अथवा खिलाड़ियों को उस राज्य की यात्रा का व्यय, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः, दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार की सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्तः, किया गया हो।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, 'सरकार' शब्द में दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य की राज्य-सरकार, राजनीतिक उपमंडल, अथवा स्थानीय अथवा सांघिक प्राधिकरण सम्मिलित माने जायेंगे।

अनुच्छेद 20

सरकारी कार्य

1. एक संविदाकारी राज्य की सरकार, द्वारा, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो उस राज्य का नागरिक है दूसरे संविदाकारी राज्य में सरकारी कार्य करने के लिए की गई सेवाओं के संबंध में भ्रदा किये गये पारिश्रमिक पर (जो पेंशन नहीं है) कर केवल प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही लगेगा।

2. किसी भी संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को भ्रवा की भांति किसी भी प्रकार की पेंशन पर कर उस संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध, किसी भी संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा लाभ के प्रयोजनार्थ चलाये जा रहे व्यापार के संबंध में की गई सेवाओं से संबंधित पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू नहीं होंगे।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, "सरकार" शब्द में दोनों संविदाकारी राज्यों की कोई भी राज्य सरकार अथवा स्थानीय अथवा सांघिक प्राधिकरण और विशेष रूप से, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंक आफ तंजानिया शामिल होंगे।

अनुच्छेद 21

गैर सरकारी पेंशन एवम् वाधिकियां

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के स्रोतों से प्राप्त की जा रही किसी भी पेंशन (अनुच्छेद 20 में उल्लिखित पेंशन से भिन्न) अथवा वाधिकी पर कर केवल प्रथम-उल्लिखित संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकता है।

2. "पेंशन" शब्द का अर्थ उस नियत-कालिक भुगतान से है जो विगत समय में की गयी सेवाओं के प्रतिफल के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान पारिश्रमिक बोट की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया गया हो।

3. "वाधिकी" शब्द का अर्थ उस उल्लिखित राशि से है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त अथवा पूरे प्रतिफल के लिये, अदायगिर्वा करने के किसी दायित्व के अधीन, जीवनपर्यन्त अथवा विनिश्चित अथवा निश्चित समयावधि के दौरान उल्लिखित समय पर देय होगी।

अनुच्छेद 22

विद्यार्थी एवम् प्रशिक्षु

1. विद्यार्थी अथवा व्यवसाय प्रशिक्षु को, जो एक संविदाकारी राज्य में जाने से तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा या और जो प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य में अनन्य रूपसे अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए उपस्थित है, निम्नलिखित के बारे में प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी:

(क) उस प्रथम-उल्लिखित संविदाकारी राज्य से बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के उद्देश्यों के लिए उसको किए गए भुगतान और

(ख) उस प्रथम-उल्लिखित संविदाकारी राज्य में "पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "भ्राय वर्ष" के दौरान जैसी भी स्थिति हो, नियोजन से प्राप्त परिलब्धि जो 10,000 रु० अथवा तंजानिया की मुद्रा में उसकी समतुल्य राशि से अधिक हो, बशर्ते कि ऐसा नियोजन प्रत्यक्षतः उसके अध्ययनों से सम्बन्धित हो अथवा उसके भरण-पोषण के उद्देश्य से ग्रहण किया गया हो।

2. इस अनुच्छेद के अधीन प्राप्त होने वाले लाभों को केवल ऐसी समयावधि के लिए दिया जाएगा जो शिक्षा अथवा लिए जा रहे प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए यथोचित रूप से अथवा व्यावहारिक रूप से आवश्यक हो, परन्तु इस अनुच्छेद के लाभ किसी भी व्यक्ति को प्रथम-उल्लिखित संविदाकारी राज्य में अपने प्रथम आगमन की तारीख से लगातार तीन वर्ष से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे।

अनुच्छेद 23

प्राध्यापक और अध्यापक

1. कोई प्राध्यापक अथवा अध्यापक जो एक संविदाकारी राज्य के किसी विश्व-विद्यालय में, अथवा उस संविदाकारी राज्य में किसी अनु-मोदित शिक्षण संस्थान में अध्यापन अथवा शोध-कार्य करने अथवा दोनों उद्देश्यों के लिए उस संविदाकारी राज्य का दौरा करता है और जो ऐसी दौरे के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा या, उसे ऐसे अध्यापन अथवा शोध-कार्य के लिए प्राप्त होने वाली किन्हीं परिलब्धियों पर उस अर्थ के लिए कर से छूट प्राप्त होगी जो उस संविदाकारी राज्य में उसके आगमन की तारीख से 24 माह से अधिक नहीं होगी।

2. यह अनुच्छेद शोधकार्य से प्राप्त भ्राय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोधकार्य मुख्य रूप से किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभों के लिए किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 22 के उद्देश्यों के लिए कोई व्यक्ति किसी संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि वह:—

(1) भारत के मामले में "पूर्ववर्ती वर्ष" में और

(2) तंजानिया के मामले में "भ्राय वर्ष" में, जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा तुरन्त पहले के पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "भ्राय वर्ष" में जैसी भी स्थिति हो, निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 के उद्देश्यों के लिए, "अनुमोदित शिक्षण संस्थान" का अर्थ उस संस्थान से है, जिस सम्बन्ध संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अनुमोदित किया गया है।

अनुच्छेद 24

भ्राय जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया

एक संविदाकारी राज्य के निवासी की भ्राय की जिन मर्कों का इस करार के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, और जिनके सम्बन्ध में उस पर उस राज्य में कर लगता है, उन पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

अध्याय IV

दोहरे कराधान के लिए अपाकरण के लिय प्रणाली

अनुच्छेद 25

दोहरे कराधान का परिहार

1. इस करार में बनाए गए विपरीत प्रावधानों को छोड़ कर दोनों में से किसी भी एक राज्य में लागू कानून अपने-अपने संविदाकारी राज्यों में भ्राय के कराधान को शासित करते रहेंगे।

2. (क) तंजानिया के कानूनों के अन्तर्गत, और इस करार के उप-बन्धों के अनुसार प्रत्यक्षतः अथवा कटीती द्वारा भारत के किसी निवासी की तंजानिया में स्थित साधनों से प्राप्त भ्राय पर भारत और तंजानिया दोनों में कर लगाया गया है, तो देय तंजानिया के कर की रकम को, उक्त भ्राय के संबंध में देय भारतीय कर के प्रति जमा मानने की स्वीकृति दी जायगी, बशर्ते कि ऐसी जमा (ऐसी जमा मानने से पूर्व यथासंगणित) भारतीय कर की उस रकम से अधिक नहीं हो, जो तंजानिया में स्थित साधनों से प्राप्त भ्राय के अनुरूप हो, लेकिन जहां ऐसा निवासी एक ऐसी कंपनी है जिसे भारत में अधिकार अथवा करना है, वहां उपर्युक्त जमा

रकम प्रथम बार कम्पनी द्वारा भारत में आयकर के प्रति देय मानी जाएगी, और शेष रकम यदि कोई हो तो वह उसके द्वारा भारत में भ्रष्टा किए जाने वाले अधिकार के प्रति जमा मानी जाएगी।

(ख) उपर्युक्त उप-धारा (क) में उल्लिखित जमा के प्रयोजन के लिए, 'तंजानिया का देयकर' शब्द में निम्नलिखित को छोड़कर ऐसी कोई भी रकम शामिल मानी जाएगी जो किसी भी वर्ष के लिए तंजानिया के कर के रूप में देय रही हो:-

- (1) आयकर अधिनियम, 1973 की प्रथम अनुसूची के भाग 2 के पैरा 1 के अधीन संजूर किए गए व्याज से कोई छूट; अथवा
- (2) आयकर अधिनियम, 1973, का द्वितीय अनुसूची के पैरा 24, 25 तथा 26 के अधीन संजूर की गई कोई पूंजी-निवेश कटौती; अथवा
- (3) आयकर की निम्नतर निगम दर विगकी आयकर अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची के पैरा 4 (क) में व्यवस्था है. अथवा
- (4) अन्य कोई भी उपबन्ध जिन्हें आर्थिक विकास के उद्देश्यों के लिए बाद में कर की किसी छूट अथवा कटौती को संजूर करने के लिए अधिनियमित किया गया हो और जिनके लिए संविधानकारी राज्यों के महत्त्व प्राधिकारी सहमत हों।

3. (क) भारत के कानूनों के अन्तर्गत, और इस करार के उपबन्धों के अनुसार में प्रत्यक्ष अथवा कटौती द्वारा तंजानिया के किसी निवासी को भारत में स्थित साधनों से प्राप्त आय पर भारत और तंजानिया दोनों में कर लगाया गया है, तो देय भारतीय कर को एकमात्र, उक्त आय के सम्बन्ध में देय तंजानिया के कर के प्रति जमा मानने की स्वीकृति दी जायेगी बशर्ते कि जमा की रकम (ऐसी जमा स्वीकृत किये जाने से पूर्व यथा संगणित) तंजानिया के कर की उक्त रकम से अधिक नहीं हो, जो भारत में स्थित साधनों से प्राप्त आय के अनुसूच है;

(ख) उपर्युक्त उप-धारा (क) में उल्लिखित जमा के प्रयोजनों के लिये 'देय भारतीय कर शब्द' में ऐसी कोई भी रकम शामिल की गयी मान ली जायेगी जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की निम्नलिखित धाराओं में निर्धारित किए गए विशेष प्रोत्साहन उपायों के अनुसार भारतीय कर छूटा दिया गया है:-

- (1) धारा 10 (4) जो किसी अनिवासी को, भारत सरकार द्वारा अधिमूर्चित किसी प्रतिभूति पर देय व्याज पर कर से छूट है;
- (2) धारा 10 (4क)--जो अनिवासी (परराष्ट्रिक) लेख की रकमों पर किसी अनिवासी को देय व्याज पर कर से छूट के बारे में है;
- (3) धारा 10 (15) (4)--जिसका सम्बन्ध निम्नलिखित को कर छूट देने से है: (क) किसी अनिवासी द्वारा भारत सरकार अथवा वहाँ के स्थानीय प्राधिकरण को उधार दिये गये धन; (ख) किसी स्वीकृत विदेशी विदेशी संस्था द्वारा भारत में किसी औद्योगिक उपक्रम को किसी ऋण-करार के अन्तर्गत उधार दिये गए धन पर व्याज; और (ग) किसी अनिवासी द्वारा भारत में किसी औद्योगिक उपक्रम को भारत से बाहर कच्चे माल अथवा पूंजी के रूप में संयंत्र तथा मशीनरी अथवा भारत में औद्योगिक विकास के लिये उधार दिये गये धन अथवा उधार मुविधायों पर व्याज;

- (4) धारा 32ए --जो जलपोतों, वायुयानों, मशीनरी अथवा संयंत्र के सम्बन्ध में निवेश छूट के बारे में है;
- (5) धारा 33ए --जो चाय के पौधों के रोपण अथवा पुनः रोपण के लिये विकास छूट के बारे में है;
- (6) धारा 35सीसी--जो ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में है;
- (7) धारा 54ई --जो पूंजीगत लाभों के बारे में है;
- (8) धारा 80एच एच--जो पिछड़े क्षेत्रों में नव स्थापित औद्योगिक उपक्रमों अथवा होटल व्यवसाय से लाभों और अभिलाषों के सम्बन्ध में कटौतियों के बारे में है;
- (9) धारा 80एचआई--जो कतिपय क्षेत्रों में नव स्थापित लघु औद्योगिक उपक्रमों से लाभों और अभिलाषों के सम्बन्ध में कटौतियों के बारे में है;
- (10) धारा 80जे--जो उपयुक्त औद्योगिक उपक्रमों अथवा जल पोतों अथवा होटलों से लाभों और अभिलाषों के सम्बन्ध में कटौतियों के बारे में है;
- (11) धारा 90के--जो उपयुक्त औद्योगिक उपक्रमों, अथवा, जलपोतों अथवा होटलों से लाभों और अभिलाषों के कारण देय लाभानों के सम्बन्ध में कटौतियों के सम्बन्ध में है;
- (12) धारा 90--जो कतिपय प्रतिभूतियों, लाभानों आदि पर व्याज के सम्बन्ध में कटौतियों के बारे में है, और
- (13) कोई भी अन्य उपबन्ध जो कर में छूट अथवा कमी करने के लिये वाक में अधिनियमित किये जाये जिनके बारे में दोनों संविधानकारी राज्यों के बीच यह सहमति हो कि वे आर्थिक विकास के प्रयोजनों के लिये है।

4. इस करार के उपबन्धों के अनुसार जिस आय पर एक संविधानकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाना है, उसे, उस संविधानकारी राज्य में लगाये जाने वाले कर की दर की संगणना के लिये हिसाब में लिया जा सकेगा।

अध्याय 5

विशेष उपबन्ध

अनुच्छेद 26

सम-व्यवहार

1. एक संविधानकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविधानकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा तस्सम्बन्धी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जायेगी, जो उस कराधान से और उन सम्बन्धित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर दैरी ही परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है।

2. एक संविधानकारी राज्य के उद्यम के, दूसरे संविधानकारी राज्य में स्थायी संस्थान पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जायेगा जो उस दूसरे राज्य के, दैरी ही परिस्थितियों में वैसी ही कार्य में प्रवृत्त उद्यम पर लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि उससे एक संविधानकारी राज्य को, ऐसे व्यवस्थितियों को, जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं, कराधान के प्रयोजनों के लिये किसी भी प्रकार की वैयक्तिक छूटें, राहतें और कटौतियाँ प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है जो कानूनन केवल उन्हीं व्यवस्थितियों को उपलब्ध है जो वहाँ के निवासी हैं,

4 एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्सम्बन्धी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जायगी, जो उस कराधान और तत्सम्बन्धी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हों, जो उस प्रथमोक्त राज्य के अन्य वैसे ही उद्यमों पर वैसे ही परिस्थितियों में लागू हो अथवा हो सकती है।

5 इस अनुच्छेद में "कराधान" शब्द का अर्थ उनही करों से जो इस करार के विषय है।

अनुच्छेद 27

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का निवासी यह समझता कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण कराधान लगाया जाता है अथवा लगाया जायेगा, जो इस करार के अनुकूल नहीं है, तो वह इन राज्यों के राष्ट्रीय नियमों द्वारा उपस्थित उपायों के होते हुए भी, जिस संविदाकारी राज्य का निवासी है, अपना मामला उसके सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। यह मामला उस कार्यवाही के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिये, जिससे ऐसे कराधान में बृद्धि होती है जो करार के अनुसार नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि बड़ा स्वयं किसी उपर्युक्त हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो, वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से, जो इस करार के अनुकूल नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। किये गये किसी भी करार को कार्यान्वित किया जायगा चाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई भी समय-सीमा क्यों न हों।

3. इस करार की व्याख्या करने अथवा उसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयाँ अथवा संकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में दोहरे कराधान के अपाकरण के लिये परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी करार में व्यवस्था नहीं है।

4. पूर्वोक्त पैरों के अधिप्राय को लेकर सहमति के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र व्यवहार कर सकते हैं। सहमत होने में जब विचारों का मौखिक आदान-प्रदान उचित प्रतीत होता हो तो ऐसे आदान-प्रदान किसी आयोग के माध्यम से किये जा सकते हैं, जिनमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

अनुच्छेद-28

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये अथवा उन करों के अपवर्धन को रोकने के लिये आवश्यक है, जो इस करार के विषय हैं। इस प्रकार आदान-प्रदान की गई सूचना अथवा दस्तावेज को गुप्त समझा जायगा, लेकिन उसे ऐसे व्यक्तियों को (जिनमें न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी शामिल हैं) प्रकट किया जा सकेगा, जो उन करों के निर्धारण, वसूली, प्रवर्तन, जॉन-पड़ताल अथवा अभियोजन से सम्बन्धित हों, जो इस करार के विषय हैं अथवा ऐसे व्यक्तियों को प्रकट किया जा सकेगा, जिनसे सूचना अथवा दस्तावेज का सम्बन्ध हो।

2 सूचना अथवा दस्तावेज का आदान-प्रदान नयी आधार पर होगा अथवा विरोध मामले के संदर्भ में अनुरोध पर या दोनों ही प्रकार में किया जा सकेगा। नयी आधार पर दी जाने वाली सूचना अथवा दस्तावेजों की मूर्ची के सम्बन्ध में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के समय-समय पर तहमनि आवश्यक होगी।

3. किन्ती भी स्थिति में पैरा 1 के उपबन्धों का वह अर्थ नहीं लगाया जायेगा जिससे कि किन्ती संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित भार डाला जाये:

- (क) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना, जिसे कोई व्यापारिक व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार सम्बन्धी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक-प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद-29

राजनयिक और मौसलीय कार्य

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के प्रावधानों के अन्तर्गत इस करार में राजनयिक अथवा मौसलीय अधिकारियों के राज्य-कर विषयक विशेषाधिकारों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय VI

उपसंहार

अनुच्छेद-30

प्रवर्तन

1 इस करार का अनुसमर्थन संविदाकारी राज्यों द्वारा उनके अपने आन्तरिक विधान के अनुसार किया जायगा। अनुसमर्थन-दस्तावेजों का आदान-प्रदान यथा संभव शीघ्र बारसलाम में किया जायेगा।

2. पुष्टीकरण के दस्तावेजों का आदान-प्रदान हो चुकने पर, यह करार :—

(क) भारत में :—

जिन कलेण्डर वर्ष में दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाता है, उसके परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी निम्न वर्ष में होने वाली आय के बारे में ;

(ख) तंजानिया में :—

जिन कलेण्डर वर्ष में अनुसमर्थन-दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाता है, उसके परवर्ती कलेण्डर वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वर्ष में होने वाली आय के बारे में ;

लागू होगा।

अनुच्छेद-31

समाप्ति

यह करार अनिश्चित काल तक लागू रहेगा, परन्तु कोई भी सविवाकारी राज्य, छठे वर्ष में अथवा जिस कलैण्डर वर्ष में अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आवान-प्रदान किया जाता है, उसके परवर्ती किसी कलैण्डर वर्ष में 30 जून, को अथवा उससे पहले, हमारे सविवाकारी राज्य को समाप्ति का नोटिस दे मकेगा और वैसी स्थिति में यह करार :—

(क) भारत में :—

जिस कलैण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती दूसरे कलैण्डर वर्ष में अप्रैल मास के प्रथम दिन अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में कर लगने योग्य आय के बारे में ;

(ख) तंजानिया में :—

जिस कलैण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उसके अगले परवर्ती कलैण्डर वर्ष में जनवरी मास के प्रथम दिन अथवा उसके बाद शुरू होने वाले आय के व के सम्बन्ध में होने वाली आय के बारे में ;

लागू नहीं रहेगा।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिये विधिवत प्राधिकृत अधीनस्थ अधिकारियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

-----मे वर्ष एक हजार नौ सौ-----के-----

-----मास के-----दिन को अग्रेजी भाषा में दो प्रतियों में किया गया।

(ए० एम० गोमालबम) (न्यु ई० आई० एम० एनी -
भारत की सरकार की ओर से तंजानिया की सरकार की ओर

(5 सितम्बर, 1979 को दस्तावेजित करार जैसा कि भारत सरकार के दिनांक 15-2-1980 के पत्र सं० डी० ए० आर०/सी० ओ० एम०से 204/3/69 तथा तंजानिया सरकार के दिनांक 3-7-1980 के पत्र सं० डी० आई० सी०/40/19/56 द्वारा सशोधित किया गया)।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 1981

INCOME-TAX

G.S.R. 559(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the United Republic of Tanzania for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has been ratified and the instruments of ratification exchanged, as required by Article 30 of the said Agreement :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profit) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

[F. No. 501-18/73-FID]

R. R. KHOSLA, It. Secy.

ANNEXURE

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION

OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the United Republic of Tanzania,

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows :

CHAPTER I

SCOPE OF THE AGREEMENT

Article I

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. The taxes to which this Agreement shall apply are :

(a) In the case of India :

(1) the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961);

(2) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964); (hereinafter referred to as "Indian Tax").

(b) In the case of Tanzania : the income tax and any other tax deemed to be an income tax under the Income Tax Act, 1973 (hereinafter referred to as "Tanzania Tax").

2. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Agreement in addition to or in place of, the taxes referred to in paragraph 1 of this Article.

3. At the end of each year, the competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any significant changes which have been made in their respective taxation law, which are the subject of this Agreement and furnish copies of relevant enactments and regulations.

CHAPTER II
DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires :

- (a) The term 'India' means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it as well as any other maritime zone referred to in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976 (Act No. 80 of 1976), in which India has certain rights and to the extent these rights can be exercised therein as if such maritime zone is a part of the territory of India ;
- (b) The term "Tanzania" means the United Republic of Tanzania, including any area outside the territorial waters of Tanzania which, in accordance with international law, has been or may be designated, under the laws of Tanzania concerning the Continental Shelf, as an area over which Tanzania may exercise sovereign rights with respect to the exploration for and exploitation of natural resources ;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Tanzania, as the context requires ;
- (d) the term "tax" means Indian tax or Tanzanian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes ;
- (e) the term "person" includes individuals, companies and all other entities which are treated as taxable units under the taxation laws in force in the respective Contracting States ;
- (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company under the taxation laws in force in the respective Contracting States ;
- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State ;
- (h) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue); and in the case of Tanzania, the Minister responsible for Finance or his authorised representative ;
- (i) the term "nationals" means :
 - (1) all individuals possessing the nationality of a Contracting State ;
 - (2) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State.

2. In the application of the provisions of this Agreement by one of the Contracting States, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that State relating to the taxes which are the subject of this Agreement.

Article 4

FISCAL DOMICILE

1. For the purpose of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the

law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his residential status for the purposes of this Agreement shall be determined in accordance with the following rules :—

- (a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (hereinafter referred to as his "centre of vital interests") ;
- (b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode ;
- (c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national ;
- (d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both the Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purpose of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include :

- (a) a place of management ;
- (b) a branch ;
- (c) an office ;
- (d) a factory ;
- (e) a workshop ;
- (f) a mine, a quarry, an oil field or other place of extraction of natural resources ;
- (g) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on ;
- (h) a building site or construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or supervisory activity continues for a period of more than six months.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise ;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display ;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise ;

- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or for collecting information, for the enterprise ;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information or for scientific research being activities solely of a preparatory or auxiliary character in the trade or business of the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State—other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 5 apply—shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first-mentioned State if :—

- (i) He has and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise ; or
- (ii) he habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to that enterprise from which he regularly fulfills orders on behalf of the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he would not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company, which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a Company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not, of itself, constitute for either company a permanent establishment of the other.

7. An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it carries on a business which consists of providing the services of public entertainers (such as theatre, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes in that other Contracting State unless the enterprise is directly or indirectly supported, wholly or substantially, from the public funds of the Government of the first-mentioned Contracting State in connection with the provision of such services.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law and usage of the Contracting State in which the property is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, oilwells, quarries and other places of extraction of natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. If an enterprise of a Contracting State, which has a permanent establishment in the other Contracting State, sells goods or merchandise of the same or similar kind as those sold by the permanent establishment or renders services of the same or similar kind as those rendered by the permanent establishment, the profits of such activities may be attributed to the permanent establishment unless the enterprise proves that such sales or services are not attributable to the activity of the permanent establishment.

3. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case, where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the ascertainment thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis.

4. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 3 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary ; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

5. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, but this does not include any expenses which, under the law of that State, would not be allowed to be deducted by an enterprise of that State.

6. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

7. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

8. The term 'business profits' means income derived by an enterprise from the carrying on of business but does not include income in the form of rents, royalties (including rents or royalties in respect of cinematographic films or video tapes for television) fees for technical services, management charges, or remuneration or fees for providing services of technical or other personnel, interest, dividends, capital gains remuneration for labour or personal (including professional) services or income from the operation of ships or aircraft.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to a share of profits from the operation of aircraft in international traffic derived by an enterprise of a Contracting State through participation in a pooled service, in a joint air transport operation or in an international operating agency.

3. For the purposes of paragraph 1, interest on funds directly connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such aircraft, and the provisions of Article 12 shall not apply in relation to such interest.

Article 9

SHIPPING

1. Income of an enterprise of one of the Contracting States derived from the other Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in that other Contracting State, but the tax chargeable in that other Contracting State on such income shall be reduced by an amount equal to 50 per cent of such tax.

2. For the purposes of paragraph 1 of this Article, income derived from the other Contracting State from the operation of ships shall mean income from the carriage of passengers, mail, livestock, or goods shipped in that other Contracting State.

3. Paragraph 1 shall not apply to profits arising as a result of coastal traffic.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would have accrued to one of the enterprises, then any profits which would have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and tax accordingly.

Article 11

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed :

- (a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the recipient is a company which owns at least 10 per cent of the shares of the company paying the dividends during the period of six months immediately preceding the date of payment of the dividends;

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares or any other item which is deemed to be a dividend or distribution of a company by the taxation law of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment of fixed base. In such a case the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the Company to persons who are not resident of that other State, or subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other State.

Article 12

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 12-1/2 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State Bank or local authority thereof, the Central Bank of that other Contracting State, or any agency wholly owned by that Government or local authority shall be exempt from tax of the first-mentioned Contracting State.

The competent authorities of the Contracting States may determine by mutual agreement any other governmental institution to which this paragraph shall apply.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and other debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the Contracting State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by that permanent establishment, then

such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including cinematograph films, and films or tapes for radio or television broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provision of this Agreement.

Article 14

CAPITAL GAINS

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other

Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services, including such gains from the alienation of such permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, gains by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships and aircraft which it operates in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in that State.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of any property other than those mentioned in paragraph 1, 2 and 3 shall be taxable only in that State.

5. The term "alienation" means the sale, exchange, transfer or relinquishment of the property or the extinguishment of any rights therein or the compulsory acquisition thereof under any law in force in the respective Contracting States.

Article 15

MANAGEMENT FEES

1. Management or professional fees arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such management or professional fees may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed twenty per cent of the gross amount of the management or professional fees.

3. The term "management or professional fees" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than to an employee of the person making the payments, in consideration for any services of a managerial, technical or consultancy nature.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the management or professional fees, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the management or professional fees arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the management or professional fees are paid, is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of article 7 or article 16, as the case may be, shall apply.

5. Management or professional fees shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the management or professional fees, whether he is a resident of that State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the management, or professional fees was incurred and such management or professional fees are borne by such permanent establishment, then such management or professional fees shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the management or professional fees paid having regard to the services for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 16

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Article 15, income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless :—

- (a) he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting States for the purpose of performing his activities, in which case so much of the income may be taxed in that other State as is attributable to that fixed base; or
- (b) he is present in the other Contracting State for the purpose of performing his activities for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in the relevant year of income and in which case so much of the income may be taxed in that other State as is attributable to the activities performed in that other State.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 17

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 18, 19, 20, 21, 22 and 23, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant year of income, and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 18

DIRECTOR'S FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 19

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 16 and 17, income derived by public entertainers (such as theatre, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised :

Provided that such income shall not be taxed in the said Contracting State if the visit of the public entertainers or athletes to that State is directly or indirectly supported, wholly or substantially, from the public funds of the Government of the other Contracting State.

2. For the purposes of this Article, the term "Government" includes a State Government, a political sub-division, or a local or statutory authority of either Contracting State.

Article 20

GOVERNMENT FUNCTIONS

1. Remuneration (not being a pension) paid by the Government of a Contracting State to any individual who is a citizen of that State in respect of services rendered in the discharge of governmental functions in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State.

2. Any pension paid by the Government of one of the Contracting States to any individual may be taxed in that Contracting State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with any business carried on by the Government of either of the Contracting States for the purposes of profit.

4. For the purposes of this Article, the term "Government" shall include any State Government or local or statutory authority of either Contracting State and in particular the Reserve Bank of India and the Bank of Tanzania.

Article 21

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension (other than a pension referred to in Article 20) or annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of services rendered in the past or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 22

STUDENTS AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on :

- (a) payments made to him by persons residing outside that first-mentioned Contracting State for the purpose of his maintenance, education or training; and
- (b) remuneration from employment in that first-mentioned Contracting State, in an amount not in excess of Rs. 10,000 or its equivalent in Tanzania currency during any "previous year" or the "year of income", as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonably or customarily required to complete the education or training undertaken, but in

no event shall any individual have the benefits of this Article for more than three consecutive years from the date of his first arrival in the first-mentioned Contracting State.

Article 23

PROFESSORS AND TEACHERS

1. A professor or teacher who visits a Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, or other approved educational institution in that Contracting State and who is, or was immediately before such visits, a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding 24 months from the date of his arrival in that Contracting State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this Article and Article 22, and individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident :

- (i) in the case of India, in the "previous years", and
- (ii) in the case of Tanzania, in the "year of income" in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" or "year of income", as the case may be.

4. For the purposes of paragraph 1, "approved educational institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 24

INCOME NOT EXPRESSLY MENTIONED

Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Agreement in respect of which he is subject to tax in that State shall be taxable only in that State.

CHAPTER IV

METHOD FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 25

AVOIDANCE FOR DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement.

2. (a) The amount of Tanzanian tax payable, under the laws of Tanzania and in accordance with the provisions of this Agreement, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of income from sources within Tanzania which has been subjected to tax both in India and Tanzania, shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such income provided that such credit shall not exceed Indian tax (as computed before allowing any such credit), which is appropriate to the income derived from sources within Tanzania; so, however, that where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesaid shall be allowed in the first instance against income tax payable by the Company in India and as to the balance, if any, against surtax payable by it in India;

(b) For the purposes of the credit referred to in subparagraph (a) above, the term "Tanzania tax payable" shall be deemed to include any amount which

would have been payable as Tanzania tax for any year but for—

- (i) any exemption from tax on interest granted under paragraph 1 of the First Schedule, Part II of the Income Tax Act, 1973; or
- (ii) any investment deduction granted under paragraphs 24, 25 and 26 of the Second Schedule to the Income Tax Act, 1973; or
- (iii) the lower corporation rate of income tax provided by paragraph 4(b) of the Third Schedule to the Income Tax Act, 1973; or
- (iv) any other provisions which may subsequently be enacted granting an exemption or reduction of tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purpose of economic development.

3. (a) The amount of Indian tax payable, under the laws of India and in accordance with the provisions of this Agreement, whether directly or by deduction, by a resident of Tanzania in respect of income from sources within India which has been subjected to tax both in India and Tanzania shall be allowed as a credit against Tanzania tax payable in respect of such income provided that such credit shall not exceed the Tanzanian tax (as computed before allowing any such credit), which is appropriate to the income derived from sources within India;

(b) For the purposes of the credit referred to in subparagraph (a) above, the term "Indian tax payable" shall be deemed to include any amount by which Indian tax has been reduced by the special incentive measures set forth in the following sections of the Income-tax Act, 1961 :

- (i) Section 10(4)—relating to exemption from tax on interest payable to a non-resident on any security notified by the Government of India;
- (ii) Section 10 (4A)—relating to exemption from tax on interest payable to a non-resident on moneys in a Non-resident (External) Account;
- (iii) Section 10(15)(iv)—relating to exemption from tax of (a) non-resident in respect of moneys lent by him to the Government or local authority in India; (b) an approved foreign financial institution in respect of interest on moneys lent by it to an industrial undertaking in India under a loan agreement; and (c) a non-resident in respect of interest on moneys lent or credit facilities allowed by him to an industrial undertaking in India for the purchase outside India of raw materials or capital plant and machinery or for industrial development in India;
- (iv) Section 32 A—relating to investment allowance in respect of ships, air-crafts, machinery or plant;
- (v) Section 33A—relating to development allowance for planting or replanting of tea bushes;
- (vi) Section 35CC—relating to the rural development allowance;
- (vii) Section 54E—relating to capital gains;
- (viii) Section 80HH—relating to deduction in respect of profits and gains from newly established industrial undertakings or hotel business in backward areas;
- (ix) Section 80HHA—relating to deduction in respect of profits and gains from newly established small scale industrial undertakings in certain areas;
- (x) Section 80J—relating to deduction in respect of profits and gains from eligible industrial undertakings or ships or hotels;
- (xi) Section 80K—relating to deduction in respect of dividends attributable to profits and gains from eligible industrial undertakings or ships or hotels;
- (xii) Section 80L—relating to deduction in respect of interest on certain securities, dividends, etc., and

(xiii) Any other provisions which may subsequently be enacted granting an exemption or reduction of tax which the competent authorities of the contracting states agree to be for the purposes of economic development.

4. Income which, in accordance with the provisions of this Agreement is not to be subjected to tax in a Contracting State, may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State.

CHAPTER V SPECIAL PROVISIONS

Article 26

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourable levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

Article 27

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the, Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of

reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 28

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information or document as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or for the prevention of evasion of taxes which are the subject of this Agreement. Any information or document so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed to persons (including a court or other authorities) concerned with the assessment, collection, enforcement, investigation or prosecution in respect of the taxes which are the subject of this Agreement, or to persons with respect to whom the information or document relates.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular case or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 29

DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. The present Agreement shall be ratified by the Contracting States according to their own internal legislation.

2. The instruments of ratification shall be exchanged at Dar-es-Salaam as soon as possible.

3. Upon exchange of the instruments of ratification, the present Agreement shall have effect—

- (a) in India, in respect of income arising in any year of account commencing on or after the 1st day of January following the calendar year in which the instruments are exchanged;
- (b) in Tanzania, in respect of income arising for any year of income commencing on or after the 1st day of January following the calendar year in which the instruments of ratification are exchanged.

Article 31

TERMINATION

This Agreement shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting States may on or before the 30th of June in the sixth or any subsequent calendar year following the calendar year in which the exchange of instruments of ratification takes place, give to the other Contracting State notice of termination and in such event this Agreement shall cease to have effect—

- (a) in India, in respect of income assessable for any year of assessment commencing on or after the first day of April in the second calendar year next following the calendar year in which the notice of termination is given;
- (b) in Tanzania, in respect of income arising for any year of income commencing on or after the first day of January in the calendar year next following

the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Dar-es-Salaam this Fifth day of September one thousand nine hundred and seventy nine in English language.

(A. S. Gonsalves)

For the Government of India

(Ndugu E.I.M. Mtai)

For the Government of Tanzania.

(Agreement signed on 5-9-1979 as amended by Government of India's letter No. DAR/COM/204/3/69 dated 15-2-1980 and the Government of Tanzania's letter No. TYC/40/19/56 dated 3-7-1980).

